डिजिटल इंडिया में डिजिटल रुपया से कैशलेस अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ संचालन

डॉ. अमित अग्रवाल*

वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटल पर कोरोना महामारी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के स्वरूप को बदल डाला। डेबिट या क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल एप, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या इमिडिएट पेमेंट सर्विस, एनईएफटी, भीम या आधार पे, यूपीआई, आरटीजीएस आदि माध्यमों से एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण हो जाता है। इसी प्रतिस्पर्धा के बीच जब विश्व में क्रिप्टोकरेंसी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी दस्तावेज़ ''द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ डी-कैशिंग'' के अनुसार विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं नकद लेन-देन को सीमित करने के लिए प्रारंभिक कदम उठा चुकी है। डिजिटल लेनदेन एक समांतर तंत्र है, जो नकद लेनदेन का स्थान नहीं लेगा, अपितु विभिन्न हेतु धारकों को लाभ प्रदान करेगा। इस शोध पत्र में डिजिटल रुपया के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषित किया गया है। इसमें डिजिटल रुपया के फायदे एवं चुनौतियो को विस्तार से बताया गया है।

प्रथम प्रायोगिक परिचालन 1 नवंबर 2022 से डिजिटल रुपया - थोक खंड (e ₹-W) में आरंभ हो गया।[01] 01 दिसंबर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल रुपये रिटेल पायलट में बंद उपयोगकर्ता समूह के लिए शुरु किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अक्तूबर 2022 को प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किया था कि e ₹-R को प्रायोगिक परिचालन की शुरुआत एक महीने के भीतर शुरू किया जाएगा। टोकन-आधारित डिजिटल रुपये एवं नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से देश डिजिटल मोड में मुद्रा का भुगतान एवं प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस प्रायोगिक परिचालन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर भावी प्रायोगिक परिचालन में e ₹-R टोकन और संरचना की विभिन्न विशेषताओं और अनुप्रयोगों का परीक्षण किया जाएगा। आरबीआई द्वारा 17 जून 2022 को जारी किए गए भुगतान विजन 2025 दस्तावेज़ के अनुसार, सीबीडीसी का उपयोग घरेलू और सीमा पार भुगतान प्रसंस्करण और निपटान के लिए किया जाएगा। आरबीआई ने सीबीडीसी को खुदरा सीबीडीसी में वर्गीकृत किया है, जिसे व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों और थोक सीबीडीसी को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जिसका मुद्रा वितरण उद्देश्य और आर्थिक स्थिरता के लिए आरबीआई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच कारोबार किया जाएगा।[02] आरबीआई सब्सिडी रिसाव और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए अन्वेषण उद्देश्य से सीबीडीसी को संचालित कर रहा है।[03]

डिजिटल रुपया का अर्थ/परिभाषा

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। यह केंद्रीय बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है। एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद सीबीडीसी को तीनों पक्षों - नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा लीगल टेंडर मान्य होने के पश्चात इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। डिजिटल रुपया को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है, e₹-R एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कागज़ी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्यवर्ग में ज़ारी किया जाएगा और मध्यस्थों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। व्यापारियों को भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग किया जा सकता है।[04] e₹-R में भरोसा, सुरक्षा और निपटान के अंतिम रूप जैसी भौतिक नकदी की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। नकदी के मामले में, यह कोई ब्याज अर्जित नहीं करेगा, परंतु इसे बैंकों के साथ धन के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया दक्षता एवं पारदर्शिता को बढाने में

*सहायक प्रोफेसर (वाणिज्य), गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, रज़ानगर, (रामपुर)।

मदद करेगा। हैश कोड विकास विधि (ब्लॉकचेन तकनीक) के कारण सूचना को बदलना मुश्किल हो जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, उपयोगकर्त्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किये गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹-R के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे और मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर संग्रहीत होंगे। बैंक नोटों की तरह डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा विनियमित और विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य होंगे। डिजिटल रुपया की देयता आरबीआई के पास है। डिजिटल मुद्रा को पेश करने का प्रमुख कारण वर्तमान परिचालन लागत को कम करना, लचीलापन एवं दक्षता लाना है। आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के दौरान डिजिटल रुपये का प्रयोग सीमा पार लेनदेन में भी करेगा।[05]

केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस पायलट प्रोजेक्ट में चरण-वार भागीदारी के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है। आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं एवं शहरों को शामिल किया जाएगा।

तालिका 1: पायलट में चरण-वार भागीदारी

प्रथम चरण		द्वितीय चरण	
सम्मिलित शहर	**सम्मिलित बैंक**	**सम्मिलित शहर**	**सम्मिलित बैंक**
मुंबई नई दिल्ली बेंगलुरु और भुवनेश्वर	भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट	अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला	बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

डिजिटल रुपए के प्रकार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल रुपए को दो व्यापक श्रेणियों - खुदरा और थोक में विभाजित किया है।

तालिका 2

डिजिटल रुपया - खुदरा	डिजिटल रुपया - थोक
खुदरा ई-रुपया नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जो मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन के लिए है। इसका उद्देश्य सभी निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय, उपभोक्ताओं और व्यवसायों के उपयोग के लिए उपलब्ध होना है। भुगतान तथा निपटान के लिये सुरक्षित धन प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता है । लेनदेन व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) दोनों प्रकार से हो सकता हैं। डिजिटल करेंसी के लेनदेन की गोपनीयता रखी जाएगी।	थोक सीबीडीसी को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य इंटरबैंक ट्रांसफर और थोक लेनदेन के निपटान के लिए है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और पूँजी बाजार में बैंकों द्वारा किये गए वित्तीय लेनदेन के लिये निपटान प्रणालियों को परिचालन लागत, संपार्श्विक तथा तरलता प्रबंधन के उपयोग के मामले में अधिक कुशल एवं सुरक्षित बनाने की क्षमता है। ई ₹-W के उपयोग से अंतर-बैंक बाजार को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा ने कहा, ''भारतीय रिज़र्व बैंक का पायलट प्रोजेक्ट ''रिटेल डिजिटल रुपया'' एक गेम चेंजर है, इसके प्रभाव टिकाऊ होंगे, जो बहुत कम लागत पर बेहतर मौद्रिक संचरण सुनिश्चित करेंगे। डिजिटल रुपया नवाचार भी है, जो प्रचलन में भारतीय भौतिक मुद्रा को सहयोग करेगा।"

परिचर्चा एवं परिणाम

1. डिजिटल रुपए के अतिरिक्त ऑनलाइन धन हस्तांतरण के अन्य माध्यम

तालिका 3: भुगतान प्रणाली संकेतक - विश्लेषणात्मक [वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)]

मद	मद मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
अ. निपटान प्रणाली						
सीसीआईएल संचालित प्रणाली	36	36	28	11,65,51,038	13,41,50,192	16,19,43,141
ब. भुगतान प्रणाली						
1. बड़े मूल्य का क्रेडिट ट्रांसफर - आरटीजीएस	1,366	1,507	1,592	13,56,88,187	13,11,56,475	10,55,99,849
खुदरा खंड						
2. क्रेडिट ट्रांसफर	1,18,481	2,06,506	3,17,852	2,60,90,471	2,85,62,857	3,35,22,150
2.1 एईपीएस (फंड ट्रांसफर)	11	10	11	501	469	623
2.2 एपीबीएस (APBS)	14,949	16,766	14,373	86,226	99,179	1,12,747
2.3 ईसीएस क्रेडिट	54	18	0	13,235	5,145	0
2.4 आईएमपीएस	17,529	25,792	32,783	15,90,257	23,37,541	29,41,500
2.5 एनएसीएच क्रेडिट	8,834	11,290	16,450	7,29,673	10,43,212	12,32,714
2.6 एनईएफटी	23,189	27,445	30,928	2,27,93,608	2,29,45,580	2,51,30,910
2.7 यूपीआई	53,915	1,25,186	2,23,307	8,76,971	21,31,730	41,03,658
3. डेबिट ट्रांसफर/डायरेक्ट डेबिट	4,914	7,525	10,456	5,24,556	7,19,708	8,72,552
3.1 भीम आधार पे	68	91	161	815	1,303	2,580
3.2 ईसीएस डेबिट	9	1	0	1,260	39	0
3.3 एनएसीएच डेबिट	4,830	7,340	9,630	5,22,461	7,18,166	8,68,906
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ)	6	93	650	20	200	913
4. कार्ड भुगतान	61,769	72,384	57,841	11,96,888	14,34,814	12,93,822
4.1 क्रेडिट कार्ड	17,626	21,773	17,641	6,03,413	7,30,895	6,30,414
4.2 डेबिट कार्ड	44,143	50,611	40,200	5,93,475	7,03,920	6,62,667
5. प्रीपेड भुगतान साधन	46,072	53,318	49,392	2,13,323	2,15,558	1,97,695
6. कागज आधारित उपकरण	11,238	10,414	6,704	82,46,065	78,24,822	56,27,189
कुल - खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	2,42,473	3,50,147	4,42,229	3,62,71,303	3,87,57,759	4,15,12,514
कुल भुगतान (1 से 6)	2,43,839	3,51,654	4,43,821	17,19,59,490	16,99,14,234	1471,12,363
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	2,32,602	3,41,240	4,37,118	16,37,13,425	16,20,89,413	14,14,85,173

स्रोत: https://m.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx ?Id=1322, आरबीआई।

नोट: 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।

2. सीबीएलओ, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार और रेपो लेनदेन और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन के दोनों चरण शामिल हैं। 5 नवंबर, 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को बंद कर दिया और सिक्योरिटीज सेगमेंट के तहत ट्राइपार्टी रेपो को चालू कर दिया।

3. कार्ड के आंकड़े बिक्री के बिंदु (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए हैं।

4. संख्याओं को राउंड ऑफ करने के कारण हो सकता है कि कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर न हों।

2. ग्राहकों में डिजिटल रुपये के संबंध में क्षेत्रदार जागरूकता

रेखा चित्र 1

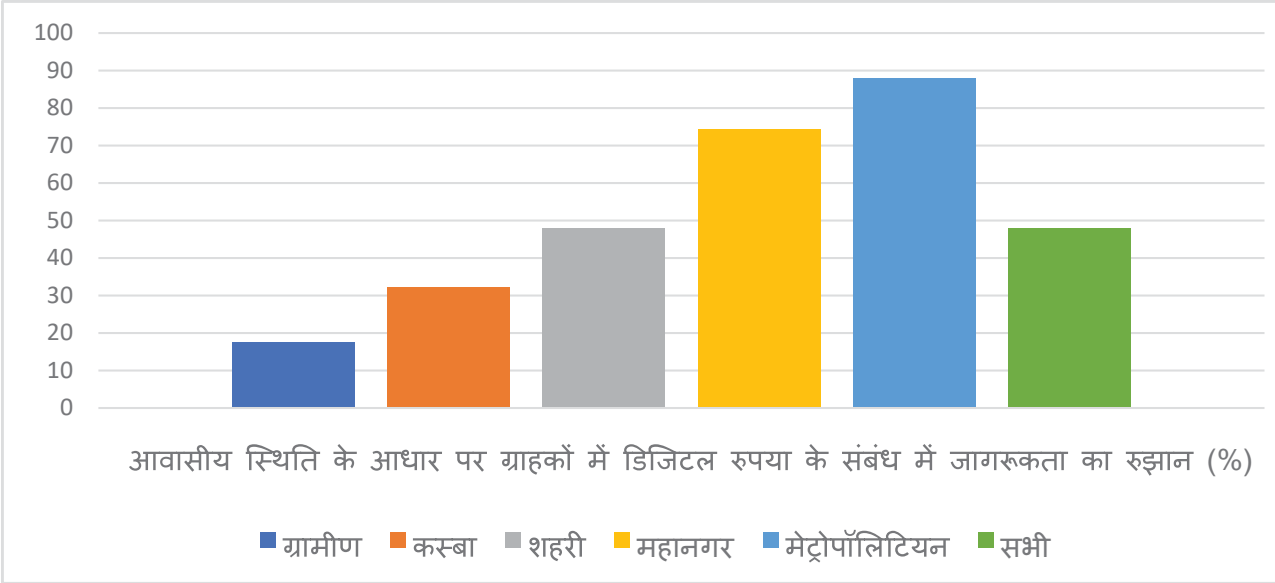

स्रोत: स्वत सर्वेक्षण

रेखा चित्र 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है डिजिटल रुपए के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के बैंक ग्राहक अधिक जागरूक हैं। डिजिटल रुपए के संबंध में जागरूकता का रुझान मुंबई में उत्तरदाताओं के आधार पर शत-प्रतिशत था, जबकि दिल्ली में 90 प्रतिशत था। शिमला, बंगलुरु, लखनऊ, पटना, नोएडा, गाजियाबाद तथा वाराणसी 07 महानगरों में डिजिटल रुपए की जागरूकता 74.28% है। रामपुर, अमरोहा, पीलीभीत, सम्भल, हापुड़, नैनीताल, जम्मू, इटारसी, कपूरथला और कोटा शहरी क्षेत्रों में 48% है। कस्बों में 32% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 17.5% है।

3. क्या डिजिटल रुपया का परिचालन विभिन्न हितधारकों के लिए लाभदायक है?

सीबीडीसी का उद्देश्य बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन एवं प्रोत्साहन करना, भौतिक नकदी प्रबंधन की लागत को कम करना, कुशल मौद्रिक भुगतान प्रणाली बनाना एवं वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाना है।[06] सीबीडीसी का प्रचलन, भौतिक मुद्रा के मुद्रण (प्रिंटिंग) पर होने वाला व्यय (लगभग ₹4,984.80 करोड) को कम कर देगा। यह व्यय सामान्यत: आम जनता, व्यवसाय, बैंक एवं आरबीआई द्वारा वहन किया जाता है।[07] एक बार e₹-R व्यक्तिगत वॉलेट में स्थानांतरित हो जाने के बाद, नाम को गुप्त बनाए रखने के लिए बैंकों द्वारा व्यवस्था की जाएगी, ताकि छोटे मूल्य के लेनदेन का पता नहीं लगाया जाएगा।[08] इसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन को निपटाने के लिए किया जाएगा। यह लेन-देन की लागत में कटौती करने और निपटान गारंटी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रोकने या निपटान जोखिम को कम करने के लिए मदद करेगा।[09] e₹-R वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर होगा जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से मध्यस्थता वाली भुगतान प्रणालियों में तरलता और क्रेडिट जोखिमों की एकाग्रता को कम करने में मदद कर सकता है।[10]

तालिका 4: डिजिटल रुपया के लाभ

क्र.सं.	लाभ	रैंक
क	तेजी से बदलते परिवेश में बेहतर विकल्प देने के लिए।	01
ख	यह आगे की सोच को प्रोत्साहित करता है।	02
ग	प्रदाता द्वारा तेज फोकस करने के लिए।	03
घ	परियोजना दृष्टि की स्पष्टता के लिए।	04
ङ	संसाधनों का तर्कसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए।	05
च	प्रदर्शन स्तर बढ़ाने के लिए।	06
छ	समन्वय में सुधार करने के लिए।	07
ज	यह गतिविधियों के नियंत्रण के लिए एक ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।	08
झ	अनिश्चितताओं के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है।	09
ञ	यह व्यक्तियों के व्यवहार को एकीकृत करने में मदद करता है।	10

स्रोत: स्वत: सर्वेक्षण

तालिका 4: डिजिटल रूपया के लाभ के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वैश्विक वित्तीय परिदृश्य तेज गति से बदल रहा है। डिजिटल रुपया बैंकिंग लेन-देनों में एक बेहतर विकल्प होगा, जिसे उत्तरदाताओं ने प्रथम श्रेणी दी है, उसके पश्चात द्वितीय श्रेणी में भविष्य की सोच को प्रोत्साहित करना है। डिजिटल रुपया बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हितधारको को भुगतान विकल्प पर फोकस प्रदान करने के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है जिसके कारण उत्तरदाताओं ने इसे तृतीय श्रेणी में रखा है। अन्य रैंक निम्न है- आरबीआई के नियंत्रण में डिजिटल रुपया परियोजना संचालित की गई है जिसकी एक स्पष्ट धारणा है। डिजिटल रुपए के संचालन से भुगतान व्यवस्था में मितव्ययिता आएगी जिससे संसाधनों का अन्य कार्य में तर्कसंगत आवंटन हो सकेगा। डिजिटल रुपया ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में उपस्थित विभिन्न हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाने के प्रयासों को तीव्र करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय करने का प्रयास करेगा जिससे डिजिटल रुपए का परिचालन आसान होगा। डिजिटल रुपया भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन होने के कारण लेनदेन गतिविधियों का नियंत्रित रखेगा, जो ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। डिजिटल रुपए के ढांचे के अंतर्गत निर्धारित बैंक ऐप के माध्यम से लेनदेन को संचालित करेंगे। धन हस्तांतरण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा जो अनिश्चितताओं को खत्म कर देगा। डिजिटल रुपया के माध्यम से ग्राहकों के व्यवहार को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि डिजिटल मुद्रा के परिचालन उपयोग से अंतर-बैंक बाजार अधिक कुशल होगे, सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटान होगा। केंद्रीय बैंक मुद्रा में निपटान से लेनदेन लागत कम होगी। निपटान जोखिम को कम करने के लिए निपटान गारंटी अवसंरचना या संपार्श्विक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आगे चलकर, डिजिटल मुद्रा के साथ संचालन के सबसे बड़े लाभों में से एक यह है कि इस प्रायोगिक परिचालन से मिले अनुभव के आधार पर भावी प्रायोगिक परिचालन के लिए अन्य थोक लेनदेन और सीमापारीय भुगतान पर ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल मुद्रा दो विदेशी देशों के बीच लेनदेन शुल्क को कम करके धन के गैर-वाणिज्यिक हस्तांतरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये गैर-वाणिज्यिक धन कई देशों में आर्थिक विकास के सबसे बड़े ड्राइवर रहे हैं। यह व्यापार को आसान बना देगा, पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाना स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। यह साइबर-आपराधिक गतिविधियों को भी कम करेगा। व्यावसायिक संगठन डिजिटल मुद्रा के प्रचलन से सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। भारत, सिक्कों और कागज के रूप में धन छपाई पर बहुत सारे संसाधन खर्च करता है। डिजिटल रुपए के प्रचलन में आने से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बचत होगी। डिजिटल रुपया नए अवसर प्रदान करेगा और नकदी के रसद प्रबंधन के बोझ को कम करके फिनटेक क्षेत्र में क्रांति लाएगा। इसके अलावा, डिजिटल रुपया मुद्रा, काले धन और भ्रष्टाचार की जालसाजी को रोकेगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के ज़रिये किये गए आर्थिक लेन-देन ब्लैक मनी के प्रचलन को खत्म कर सकता है। डिजिटल रुपया प्रचलन में आने से टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी, क्योंकि प्रत्येक डिजिटल लेन-देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं। ब्लैक मनी इकट्टा करना, नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली आदि आपराधिक गतिविधियों को मुक्ति दिलाने में डिजिटल रुपया सहायक सिद्ध होगा।

4. क्या डिजिटल रुपया का परिचालन सार्वजनिक निधि का एक बड़ा व्यय है

रेखा चित्र 2: (उत्तरदाताओं का सहमति प्रतिशत)

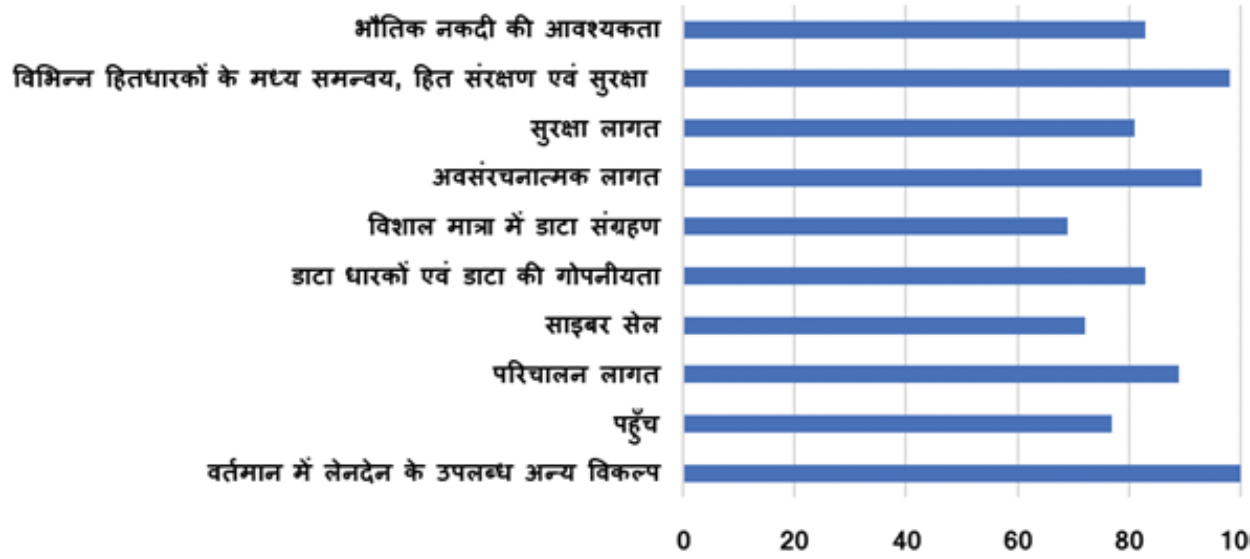

स्रोत: स्वत: सर्वेक्षण

रेखा चित्र 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में वर्तमान में धन हस्तांतरण के अनेक विकल्प उपलब्ध है। विश्लेषणात्मक तालिका 3 में भुगतान के ऑनलाइन विकल्पों का वर्णन किया गया है। डिजिटल रुपया भुगतान व्यवस्था अभी तक सभी बैंकिंग संस्थाओं और ग्राहकों की पहुँच में नहीं है। हितधारकों तक डिजिटल रुपये की पहुंच बनाने के लिए बैंकिंग सेक्टर में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी, इस कथन से 70% उत्तरदाता सहमत है। डिजिटल रुपया परियोजना के संचालन के लिए परिचालन लागत में वृद्धि होगी, इस कथन से 89% उत्तरदाता सहमत है। डिजिटल रुपया को सुरक्षित करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में साइबर सेल को मजबूत करना होगा और कई स्थानों पर नए साइबर सेल स्थापित करने होंगे। डिजिटल रुपया का उपयोग करने वाले डाटा धारको की सूचनाओं को गोपनीय रखने के लिए विशाल मात्रा में डाटा संरक्षण की व्यवस्था करनी होगी जिससे अवसंरचना लागत में वृद्धि होगी। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल रुपया को संरक्षित रखने के लिए सुरक्षा लागत में अत्यधिक वृद्धि होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और बैंकिंग सेक्टर के विभिन्न हित धारको के मध्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित करना एक जटिल कार्य है, बैंकों द्वारा अपने हितों को वरीयता दी जाती है जिससे कई बार सुरक्षा में सेंध लग जाती है। ग्रामीण एवं निर्धन व्यक्ति भौतिक नकदी को वरीयता देते हैं। कई प्रकार के कार्य को कराने के लिए भौतिक नकदी की आवश्यकता पड़ती है। रेखा चित्र में उत्तरदाताओं के सहमति प्रतिशत को दर्शाया गया है।

डिजिटल रूपया सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाकर देश को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकता है।

तालिका 5: भारत में डिजिटल रुपया परियोजना के लिए चुनौतियाँ

क्र.सं.	चुनौतियों का बिंदु	रैंक
क	लगभग 950 मिलियन भारतीय अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पर नहीं हैं।	01
ख	डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।	02
ग	एनओएफएन (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर) के 67% बिंदु गैर-कार्यात्मक हैं/ 250000 ग्राम पंचायतों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नहीं है।	03
घ	भारत में इंटरनेट स्पीड बहुत कम है।	04
ङ	धीमा और विलंबित डिजिटल अवसंरचना विकास।	05
च	भारत में सरकारी परियोजनाओं में निजी भागीदारी कम है।	06
छ	50000+ गांव मोबाईल कनेक्टिविटी से वंचित।	07
ज	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियाँ/ पारदर्शिता की कमी।	08
झ	छिपे हुए मालवेयर के निरीक्षण के लिए पर्याप्त कौशल की कमी।	09
ञ	अत्यधिक प्रचलित भाषाएं।	10

स्रोत: स्वत: सर्वेक्षण और डिजिटल इंडिया पर एसोचैम-डेलॉयट की रिपोर्ट, नवंबर-2016

 # अकामाई की रिपोर्ट (तीसरी तिमाही 2016) इंटरनेट स्पीड पर भारत दुनिया में 105वें स्थान पर है।

तालिका 5: भारत में डिजिटल रुपया परियोजना की चुनौतियाँ के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि एसोचैम-डिलॉयट द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार, ''अभी तक लगभग 950 मिलियन भारतीयों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।'' यूएन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक सूचकांक पर 167 देशों में से 131वें स्थान पर रखा गया है। इसीलिए उत्तरदाताओं ने इस कारक को प्रथम रैंक प्रदान की है। सीबीडीसी के बारे में नागरिकों में जागरूकता की कमी है। लोग अक्सर इसे क्रिप्टोकरंसी के साथ भ्रमित करते हैं। अज्ञानता, उपयोग करना कठिन बना देती है। ओसामा मंजर (डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संस्थापक-निदेशक) के अनुसार, प्रायोगिक स्तर पर भी एनओएफएन बिंदुओं का 67% गैर-कार्यात्मक है। देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना है। डब्ड द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 110 देशों में 59वें स्थान पर है। विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल रैंकिंग 2018 (एल.पी.आई.) रिपोर्ट में भारत को 44वां स्थान दिया गया, जिसमें अवसंरचना में 52वां स्थान दिया गया है, जो कमजोरी को अंकित करता है। भारत के बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचैन का समर्थन करने वाले बैंक अभी कम है उन्हें उन्नयन की उच्च लागत को वहन करना पड़ सकता है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा (अप्रैल 13, 2017) में कहा, ''लगभग 50,000 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है।'' मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या एक प्रतिष्ठान, अवैध धन को जटिल चैनलों के माध्यम से कानूनी धन में परिवर्तित करता है। सीबीडीसी सिस्टम में मूल स्रोत को ज्ञात करना एक कठिन कार्य है जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग के केस बढ़ने की संभावना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक लक्षित देश है, और इनमें से 58 प्रतिशत हमले वित्तीय सेवा क्षेत्र को लक्षित करते हैं। हमलावर बैंकों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से वित्तीय डाटा चुराने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जैसे - फ़िशिंग, नकली ईमेल, वॉयस फिशिंग, नकली वेबसाइट, सोशल इंजीनियरिंग, कार्ड स्किमिंग, लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट के नकली संस्करण, नकली मोबाइल ऐप, नकली एसएमएस, प्वाइंट-ऑफ-सेल मालवेयर। 2001 की जनगणना के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं के साथ, भारत में 1,600 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि केवल 8% भारतीय ही अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। फेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने हाल ही में ''साइबर जोखिम'' को वित्तीय स्थिरता से संबंधित उनकी नंबर एक चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया है, और हाल ही में यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट ने विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों को सीबीडीसी विकसित नहीं करने के संभावित कारणों के रूप में वर्णित किया है। गलत हाथों में, आए डाटा का इस्तेमाल नागरिकों के निजी लेन-देन की जासूसी, व्यक्तियों और संगठनों के बारे में सुरक्षा-संवेदनशील विवरण एवं पैसे चोरी करने के लिए किया जा सकता है। ई-रुपया आवश्यक रूप से वित्तीय समावेशन की समस्या को हल नहीं करता है, जो इस बिंदु पर साक्षरता अंतर और डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में अविश्वास द्वारा प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा डिजिटल रुपया परियोजना शुरू करना एक सराहनीय कदम है। केंद्रीय बैंक सीबीडीसी प्रणाली के सभी पहलुओं जैसे मुद्रा जारी करना, खाता रखना और लेनदेन सत्यापन का प्रबंधन करेगा। जनसंख्या के एक बड़े भाग को बैंकिंग नेट लाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए और असंगठित क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर डिजिटल रुपए के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। डिजिटल रुपए के प्रयोग के लिए सरकार को विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। डिजिटल रुपए के प्रयोग से सरकार का कर दायरा बढ़ेगा जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिटल भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार एवं प्रासंगिक बनाने पर आरबीआई को बल देना होगा।

References

[01]. "India central bank to start pilot of digital rupee on Nov 1". Reuters. 31 October 2022. Retrieved 4 November 2022.

[02]. Sarkar, Gargi (23 June 2022). "India's CBDC Set To Take Off: From Cross-Border Payments To Subsidies — Here Are The Use Cases On The Table". Inc42 Media. Retrieved 23 June 2022.

[03]. "Payments Vision 2025" (PDF). Reserve Bank of India. 17 June 2022. Retrieved 20 June 2022.

[04]. Bose, Arghanshu (30 November 2022). "Explained: What is RBI digital rupee and how to use it". The Times of India. Retrieved 30 November 2022.

[05]. Ray, Anulekha (4 November 2022). "RBI CBDC: Digital Rupee pilot starts from November 1; SBI, HDFC, 7 other banks to participate in wholesale launch". The Economic Times. Retrieved 4 November 2022.

[06]. "The e₹ is on the way as RBI gears up for a pilot launch of its own digital currency". Moneycontrol. 10 October 2022. Retrieved 4 November 2022.

[07]. Kaushal, Teena Jain (1 November 2022). "RBI's Digital Rupee pilot launch today: Here are 10 things to know". Business Today. Retrieved 4 November 2022.

[08]. Shukla, Saloni (1 December 2022). "e-Rupee may offer same anonymity as dealing in cash". The Economic Times. Retrieved 3 December 2022.

[09]. "First pilot of Digital Rupee to commence on Tuesday: RBI - Times of India". The Times of India. 31 October 2022. Retrieved 31 October 2022.

[10]. D, Priyadarshini (4 November 2022). "UPI powers India's digital transactions. RBI's eRupee is compelling but must argue retail use". The Print. Retrieved 5 November 2022.

https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?ID=46546

https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PressReleases.aspx?ID=46383

https://taxguru.in/rbi/rbi-digital-rupee-launch.html

☯

Bank Quest included in UGC CARE List of Journals

IIBF's Quarterly Journal, Bank Quest has been included in UGC CARE list of Journals. The University Grants Commission (UGC) had established a "Cell for Journals Analysis" at the Centre for Publication Ethics (CPE), Savitribai Phule Pune University (SPPU) to create and maintain the UGC-CARE (UGC – Consortium for Academic and Research Ethics). As per UGC's notice, research publications only from journals indexed in UGC CARE list should be used for all academic purposes.